● Publishing Date : July 31, 2018 ● Total Number of Pagesa : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जुलाई, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 15, अंक : 2

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय वर्षा ऋतु चल रही है परन्तु उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार राज्यों में वर्षा बहुत कम हो रही है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो फिर भी कुछ वर्षा ठीक ठाक है परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो करीब करीब सूखे की स्थिति भी बन गई है। आशा है आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होगी।

आलू की निकासी सामान्य ही चल रही है। अभी निकासी ने गति नही पकड़ी है। आलू के रेट भी सामान्य ही है उठान की तरफ नहीं।

हमें अभी तक हासन की फसल का कोई पुष्ट समाचार नहीं मिला है केवल इतना ज्ञात हुआ था की हासन में इस वर्ष आलू की बुआई अच्छी हो रही है। उत्पादन के बारे में कोई अनुमान नहीं है। यह सब वर्षा पर निर्भर करता है। हासन पहाड़ी क्षेत्र है अधिक वर्षा व कम वर्षा दोनों ही बहुत जल्दी फसल को नुकसान पहुँचा सकते है। हासन की फसल उत्तर प्रदेश के आलू को बहुत जबरदस्त असर डालती है। हासन के बारे में सही अनुमान करीब 15 दिन बाद मिलेगा। →

इस समय आर्द्रता काफी ऊँची है। अतः शीतगृहों को अपने कक्षों में तापमान पर विशेष ध्यान देना होगा। तापमान के जरा से भी उठने से अर्थात 36^0 डिग्री तापमान से ऊपर जाने में अंकुरण की समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए तापमान नीचा रखे 33^0 / 34^0 फारेहनहाइट पर अपने कक्षों को चलाए। शीतगृह कक्षों में हवा के संचालन पर विशेष ध्यान देना होता है। इस समय 15 / 20 प्रतिशत आलू कक्षो से निकल चुका है, इसलिए बढ़िया तरीके से पल्टाई की जा सकती है, गैलरी छोटी की जा सकती है और यदि जरूरत हो तो आलू की छल्ली भी कम की जा सकती है। विशेष ध्यान दें, आलू महँगा है, आप पर बोझा भी काफी आ जाता है।

अगले माह से आलू तेज निकलने लगेगा अतः आलू के सूखाने के शेड की तैयारी पूरी कर ले। आलू सूखाने वाले पंखो को जॉच ले की वह सही दशा में है या नहीं क्योकि आलू की निकासी,आलू सूखाने वाले शेड पर निर्भर होती है। जितनी बढ़िया आलू सुखाने की सुविधा आप देंगे, आलू किसानों के सौदे फटाफट होगे, उतना ही किसान अगले वर्ष आपके यहा आने के लिए आर्कषित होगा।

हम अनेक बार लिख चुके है कि किसानो के आलू की बिक्री में शीतगृहो को नाम मात्रा के लिए भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस से पूरी तरह से बचे। कुछ ना करते हुए भी किसान शीतगृहो पर आक्षेप लगाते है कि शीतगृहस्वामियो ने उसका आलू व्यापारी के साथ मिल कर कम रेट पर बेच दिया। आप केवल अपने भाड़े का पैसा जमा करे। बाकी बचा हुआ पैसा किसान हाथ के हाथ आपके पास रखे।

यह बात तो मानी जा सकती है कि आप के भाड़े की रकम तक या आप पर दिए हुए लोन पर आप का हस्तक्षेप ठीक है परन्तु कुछ शीतगृह इसका पालन नहीं करते और पूरी रकम का भुगतान विलम्ब से करते है। किसान झूठी सच्ची शिकायतें करता है और इस से शीतगृहों की छवि खराब होती है।

उद्योग बन्धु की उच्च स्तरीय बैठक :

प्रदूषण उपकर सम्बन्धी :

दिनांक 22.6.2018 को उद्योग बन्धु की मीटिंग मे ज्ञात हुआ कि शीतगृहों पर शुरू से ही वायु उपकर नही लगाया गया है। जहॉ तक जल उपकर का सवाल है, वह वर्ष 2017, जुलाई माह से लागू नही है क्योकि वर्ष 2017 से जी.एस.टी लागू हो गया है। इसके साक्ष्य के रूप मे उन्होने मीटिंग के Minutes मे रिकार्ड कर दिया है।

→

Goods And Services Tax (GST)

Abolition of cesses

Following cesses have been abolished by the Taxation Laws (Amendment) Act :

- Education Cess on excisable goods
- Secondary & Higher Educatioh Cess on excisable goods
- Cess on cement
- Cess on strawboard
- Cess on rubber levied under the Rubber Act, 1947
- Cess on automobile levied under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951
- Cess on tea under the Tea Act, 1953
- Cess on coal levied under the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.
- Cess on bidis levied under the Bidi Workers' Welfare Cess Act, 1976
- **Cess on water consumed by certain industries and by locai authorities levied under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977**
- Cess on sugar levied under the Sugar Cess Act, 1982 and the Sugar Development Fund Act, 1982
- Cess on jute goods manufactured or produced wholly or in part levied under the Jute Manufacturers Cess Act, 1983
- Clean Energy Cess levied under the Finance Act, 2010
- Swachh Bharat Cess levied under the Finance Act, 2015
- Infrastructure Cess and Krishi Kalyan Cess levied under the Finance Act, 2016.

शीतगृह में क्या तापमान या आद्रर्ता रखने सम्बन्ध में :

Kundli Cold Storage Assosiation ने अपने Energy Profile में तापमान, आर्द्रता सम्बन्धी यह सूचना छापी है जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी सम्बन्ध में हमने पहले भी यह सूचना छापी थी। हो सकता है दोनों में थोड़ा बहुत अन्तर हो परन्तु मुख्यतः यह तापमान वा आर्द्रता के मानक सही ही होते हैं।

→

Temperature requirements for common commodities

Product	Temperature		RH (%)
	^{0}C	^{0}F	
Apples	-1-4	30-40	90-95
Apricots	-0.5-0	31-32	90-95
Bananas, green	13-14	56-58	90-95
Beans, dry	4-10	40-50	40-50
Beans, green or snap	4-7	40-45	95
Beans, lima, in pods	5-6	41-43	95
Blackberries	-0.5-0	31-32	90-95
Cabbage, early	0	32	98-100
Cabbage, late	0	32	98-100
Cashew apple	0-2	32-36	85-90
Cherries, sour	0	32	90-95
Cherries, (sweet)	-1-0.5	30-31	90-95
Garlic	0	32	65-70
Kiwi fruit	0	32	90-95
Lychees	1.5	35	90-95
Mangoes	13	55	85-90
Mushrooms	0	32	95
Onions, (dry)	0	32	65-70
Peaches	-0.5-0	31-32	90-95
Pears	-1.5-0.5	29-31	90-95
Peas, green	0	32	95-98
Peppers, Chilli (dry)	0-10	32-50	60-70
Plums and prunes	-0.5-0	31-32	90-95
Pomegranates	5	41	90-95

Product	Temperature		RH (%)
	^{0}C	^{0}F	
Potatoes, (early crop)	10-16	50-60	90-95
Potatoes, (late crop)	4.5-13	40-55	90-95
Sweet potatoes	13-15	55-60	85-90
Tamarinds	7	45	90-95
Tomatoes, (mature-green)	18-22	65-72	90-95
Tomatoes, (firm-ripe)	13-15	55-60	90-95

Source : McGregor B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of Transporation, Agricultural Handbook; 668 pp.

अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :

इस विषय को हमने उद्योग बन्धु में उठाया था और बताया था कि अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में शीतग्रहो को बहुत परेशानी हो रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मानक बता दिए जाते है और इतनी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया जाता है जो शीतगृहो के लिए उसे पूरा कर पाना सम्भव ही नहीं है, जैसे शीतगृहो को बहुमंजिला इमारत में गिन लेते है जबकि शीतगृह एक मजिल ही होते है। बहुमंजिला इमारत का कानून 15 Meter से अधिक ऊचाई पर लगता है जबकि शीतगृह 15 मीटर से कम ही होते है। शीतगृहो पर Storage कानून लगा दिया जाता है जबकि वह Storage न के Cold Storage होते है। स्टोरेज का अर्थ होता है भण्डार जहा पर विस्फोटक सामग्री भी रखी जा सके जैसे petroleum पदार्थ, गैस, पटाखे आदि इस के साथ ही गेहूँ या चावल के भण्डारण के लिए भी नियम अलग होते है। वह सब शीतगृहों पर लगा दिए जाते है। इसके साथ हमने यह भी बताया कि अग्नि शमन के नियम लागू होने से पहले के बने शीतगृहों का उनका पालन करवाना कैसे सम्भव होगा।

इन सब बातों को मानते हुए, उद्योग बन्धु की ओर से गृह विभाग को यह आदेश दिए गए कि शीतगृहों के लिए अलग से नए सिरे से नए नियम बनाये जाए। इस सम्बन्ध में गृह सचिव से मीटिंग होना बाकी है। जैसे ही नए नियम बनेंगे हम सूचित करेगें।

उत्तर प्रदेश सरकार के फैक्ट्री एक्ट के सम्बन्ध में

फैक्ट्री एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं, नए संशोधन के अनुसार अब 20 कर्मचारी या उसमे अधिक पर ही फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। इस तरह से जिन शीतगृहों के बीस से कम कर्मचारी हैं वह →

फैक्ट्री एक्ट की परिधि से बाहर हो जाते हैं। दूसरा नियम यह भी था कि यदि कोई भी जगह पर 10 से अधिक कर्मचारी विद्युत की मदद से किसी वस्तु का निर्माण करते है वह भी फैक्ट्री एक्ट की परिधि में आते है। शीतगृह तो किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करते अतः हम समझते है कि अधिकांश शीतगृह फैक्ट्री एक्ट की परिधि से बाहर है परन्तु फिर भी यह बिन्दु अपने लेबर एडवाइजर से स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। इस बात को पूरा समझने के लिए हम फैक्ट्री एक्ट में क्या सुधार हुआ है वह यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

No. 202(2)/LXXIX-V-I-18-1(Ka)-08-2017

Dated Lucknow, January 29, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karkhana (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 20, 2018.

THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act No. 13 or 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

Further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Sixty eighth year of the Republic of India as follows :-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

Amendment of section 2 of Act no. 63 of 1948

2. In section 2 of the Factories Act, 1948 as amended in its application of Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (m).

(i) in sub-clause (i), for the words "ten or more", the words "twenty or more" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii) for the words "twenty or more", the words "forty or more" shall be substituted.

→

3. In section 64 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (iv) for the word 'fifty', the words "one hundred" shall be substituted. **Amendment of section 64**

4. In section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv) for the words 'seventy-five' the words 'one hundred fifteen' shall be substiuted. **Amendment of section 65**

5. In section 66 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:- **Amendment of section 66**

"Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of any factory or group or class or description of factories vary the limits laid down in this clause and such variation may authorize the employment of any woman between the hours of 7 p.m. and 6 a.m. mentioning therein the provisions for the safety and facilities of the women to be given to her."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing the safety, health, welfare, working hours, overtime leaves and other aspects of workers employed in factories.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive business atmosphere there has been growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, employment of women during night and exempting small industrial units from applicability of the Act. So, after due consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order

Virendra Kumar Srivastava

Pramukh Sachiv

The machinery or premises used for a manufacturing process, or in any other kind of work incidental to, or connected with, the manufacturing process, or the subject of the manufacturing process, [1](but does not include any member of the armed forces of the Union;]

(m) "factory" means any premises including the precints thereof-

(i) whereon ten or more workers are working, or were working, on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, or

(ii) whereon twenty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on,

But does not include a mine subject to the operation of [2][the Mines Act, 1952 (35 of 1952) or [3][a mobile unit belonging to the armed forces of the Union, a railway running shed or a hotel, restaurant or eating place;)

[4][Explanation [5][I].-For computing the number of workers for the purposes of this clause all the workers in [6][different groups and relays in a day shall be taken taken into account;]

[7][Explanation II.-For the purposes of this clause, the mere fact that an Electronic Data Processing Unit or a Computer Unit is installed in any premises or part thereof, shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof.);

(n) "occupier" of a factory means the person who has ultimate control over the affairs of the factory,

[8][***]

[9][Provided that-

(i) in the case of a firm or other association of individuals, anyone of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier;

(ii) in the case of a company, anyone of the directors, shall be deemed to be the occupier;

(iii) in the case of a factory owned or controlled by the Central Government, or any State Government, or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of the factory by the Central Government, the State Government or the local authority, as the case may be, shall be deemed to be the occupier]:

---

1. Ins. by Act 94 of 1976 (w.e.f. 26.10.1976).
2. Subs. Sfor "The Indian Mines Act, 1923 (4 of 1923)" by Act 25 of 1954
3. Subs. for "A railway running shed" by Act 94 of 1976

→

4. Explanation ins. by Act 94 of 1976
5. Renumbered by Act 20 of 1987
6. Subs. by Act 20 of 1987 (w.e.f. 1.2.1987)
7. lns. by Act 20 of 1987
8. Del. by Act 20 of 1987 (w.e.f. 1.12.1987)
9. Proviso by ibid. Ins. by Act 20 of 1987

औद्योगिक और Service Sector में लगे उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति :

इस सम्बन्ध में 2004 में सरकार ने एक नीति बनाई थी जिस से कि उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में लगे संस्थानो को आगे बढ़ाया जब सके। Policy के कुछ विशेष अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं, अतः हम इन्हें ऐसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

Highlights of the "Industrial and Service Sector Investment Policy-2004"

The Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 has been approved by the Cabinet on February 19, 2004. The Highlights of new policy are as follows -

Infrastructure

1. Creation of Industrial Infrastructure Development Fund (IIDF) with a Budgetary Provision of Rs. 50 crore. Rs. 50 crore budgetary provision will be made in the next four years also. Fund will finance and subsidize initiatives in infrastructure creation.
2. Establishment of Industrial Infrastructure Development Authority (IIDA) to manage IIDF. IIDA to work under a whole-time managing director, drawing professional personalities in its management. IIDA wil have right to collect user-charges and raise capital and to will become self-sustaining through professional project planning and implementation.
3. Creation of world class infrastructure through private partnership. Facilities like transhipment centres, integrated transport and trade centres, exhibition halls, trade centres, container depots, way-side facilities, display centres etc.;
4. Maintenance of Industrial Estates by a Co-operative Society of the entrepreneurs. The Society will receive 60% of taxes collected by the local authority and may be granted necessary financial assistance as and when necessary;

Power & Energy

5. Uninterrupted power suplies for 24 hours to Industrial Areas. IT/BT/Food Processing/ Agro-based industries involving investment of more than 10 crores and other industries involving investment of more than 50 crores will be supplied electricity throught dedicated feeders;
6. Feeders having 75 per cent or more industrial load will be deemed as industrial feeders and will be exempted from power cuts;

→

7. Dedicated feeders built at the cost of industries shall not be tapped for any other purpose, except where such industry consents to tapping of such feeders for another industrial unit under mutual agreement;
8. Captive and Co-generation to be promoted;
9. Natural gas to be promoted as an alternative source of energy;

17.3 Only one combined inspection of industries in a year;

17.4 Small scale units having less than 25 employees exempted from labour laws;

17.5 Entrepreneurs and traders having turnover upto Rs. 3 lac exempted from trade-tax registration;

17.6 Automatic approval of industrial building maps on submission except for a restricted list of highly polluting industries.

17.7. Compulsion of giving employment to land-holder in lieu of acquired land removed;

17.8 In case of recovery of dues-

17.8.1. Stamp duty to be charged on actual auction amount;

17.8.2 Recovery charges on actual amount recovered/amount of OTS only;

17.9 Breaking local truck cartels;

17.10 U.P. Shops and Establishments Act, 1962 will be amended considering the needs of Call Centres, Multiplexes, Shopping Complexes and other services facilities which keep open for 24 hours;

Other Matters

18. Appointment of Chief Industrial Development Officer in selected industrial districts;
19. Task force under the chairmanship of Industrial Development Commissioner for inquiry into complaints of harassment by officials;
20. Fast track grievance redressal system on security issues. An IG Police to be deputed on whole time basis in the office of DG Police to look into the security needs of the entrepreneurs;
21. Entrepreneurs / Trader Security Forum to be created at District level under the Chairpersonship of the District Magistrate;
22. Meeting of Udyog Bandhu at Hon'ble Chief Minister's level once in every three months;
23. Creation of Human Resource Development Fund for providing assistance to participating companies for training and development of employees. Participating companies to contribute 1/2 to 1 per cent of their wage bill according to number of employees; State Government will contribute twice such amount. Participating companies will be entitled to draw three times their contribution.

→

24. U.P. Small Industrial Units Rehabilitation Board to be created. An Act to be passed for effective implementation of Rehabilitation Board.
25. Creation of Rehabilitation Fund of Rs. 50 lac for funding 50 per cent of consultancy charges for making rehabilitation packages.

अपनी Federation Of Cold Storage Associations of India सम्मानित :

Progressive India Conclave में 8 जुलाई, 2018 को Federation Of Cold Storage Associations of India को World Wide Trusted Association of Cold Storages पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार को माननीय एस.पी. सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश और आगरा के मेयर ने मिल कर दिया, जिसे श्री राजेश गोयल ने आगरा के शीतगृहस्वामियों के साथ जाकर स्वीकार किया।

यहाँ हम एक चित्र प्रस्तुत कर रहे है जिसमें माननीय एस.पी. सिंह बघेल व आगरा के मेयर, श्री राजेश गोयल को अवार्ड देते हुए दिखाए गए है।

Koelnmesse कम्पनी द्वारा आगरा की मीटिंग का प्रचार :

Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd. जो कि Germany की Company है हमारी आगरा में सेमिनार की Exhibition में हिस्सा ले रही है। इन्होंने करीब 10,000 News letter छपवाये हैं, जिसमें उन्होंने विस्तार से Federation Of Cold Storage Associations of India और आगरा वाले प्रोग्राम का वर्णन किया है। यहाँ पर हम उनके द्वारा छपवाए हुए News letter को प्रस्तुत कर रहे हैं। →

Federation of Cold Storage Associations of India (FCAOI)

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Federation of cold storage associations of India (FCAOI) is an Federation of all India cold storage associations with its members spread across the country. There is a huge need for cold storage facilities in India leading to the formation of state level associations who look after their concerns.

The Objectives of FCAOI :

- To unite the cold storage industry in India, under the FCAOI umbrella.
- Exchange and share the latest cold storage technology among member federations within the country and outside India too.
- Organising conferences, meetings to plan and execute strategies of FCAOI; arranging the visits of various industry experts.
- To provide, make available and publish knowledge and information on different laws and legislation that impacts the cold storage industry.
- To act as a representative and liaison channel between the FCAOI and different state and central government departments. fcaoi.org

Federation of Cold storage associations (FCAOI) is glad to associate with Food Logistics India 2018, India's largest exhibition on cold chain, warehousing, transportation & logistics for the Food & beverage industry. With a network of more than 5,000 Cold storage owners across India, our federation is continuously engaged in developing the most emerging industry segment in India.

Indian cold chain industry is forecasted to grow at a CAGR of 19% during the period of 2017-2022 there by creating a need of better storage and transportation facilities. Food logistics India along with its concurrent exhibition would be an ideal platform for our industry to stay abreast of the latest technological innovations in the global market. WE wish Food Logistics India a great success!

Mahendra Swarup
(President, FCAOI & President, Cold Storage Association, Uttar Pradesh)

Federation of Cold Storage Associations of India is glad to extend its support to Food Logistics India – an International Exhibition on Cold Chain , warehousing, Transportation & logistics for the Food & Drink Industry.

Rajesh Goyal
Hon. Secretary, FCAOI

Ashish Guru
Senior Vice President, FCAOI, President, Gujarat Cold Storage Association, Gujarat

Mukesh Kumar Aggarwal
Co-ordinator Gov Affairs, FCAOI, Vice President, All India Cold Storage Association, Delhi

Rajendra Parekh
Member, FCAOI & President, Maharashtra Cold Storage Association

Lalji R. Savla
Member, FCAOI & Navi Mumbai Cold Storage Owners Welfare Association

Technical Seminar on
'Emerging Technologies in Cold Chain Industry'

Focusing on
- Innovation in cold chain industry
- Traditional Cold Storage vs Conventional Cold Storage
- Importance of Refrigeration & Transportation to Save Food

Regional Members Meet

Federation of Cold Storage Associations of India is organising an unique platform to Network with over 800 Cold Storage Owners from Across India

FCAOI – Excellence in Cold Chain Awards

Awards are for the below categories:
1. Emerging Young leader in Cold storages.
2. Dynamic leadership in Cold storages.
3. Progressive Cold Storage Facility.
4. Progressive Frozen Cold Storage Facility
5. Progressive Multi Commodity Cold Storage Facility.
6. Cold Storage Facility in Remote Areas.

Date & Venue : 27th September 2018, Bombay Exhibition Centre. Registration: Please visit http://foodlogisticsindia.com for updates.
Contact: Rohan Salian : - +91 9820461327; +91-22-28715223; r.salian@koelnmesse-india.com

आलू विकास बोर्ड के गठन से सम्बन्धित बैठक :

दिनांक 4 जुलाई, 2018 को प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें आलू उत्पादक, कोल्ड स्टोरेज ओनर्स, सरकारी अधिकारी, आलू प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के लोग उपस्थित थे और सबके सुझाव माँगे गए।

सभी आमंत्रित प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार–विमर्श एवं चर्चा के उपरान्त आलू विकास बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

- आलू विकास बोर्ड राष्ट्रीय स्तर का हो, जिससे उत्पादक एवं उपभोक्ता सभी राज्यों में आलू को विपणन के लिए आदान–प्रदान करने से सभी राज्यों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
- आलू विकास बोर्ड का गठन प्रथमतः 05 वर्ष के लिए किया जाय, जिसे प्रदेश के आलू किसानों, शीतगृहों, विक्रेता एवं निर्यातकों तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के हित के लिए उपयोगी पाये जाने पर उसे आगामी वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- आलू विकास बोर्ड प्रथम चरण में उ.प्र. के साथ–साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों को सदस्य सम्मिलित किया जाय, जिसे अगले चरण में उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्यों को बोर्ड में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जाय।
- आलू विकास बोर्ड में प्रगतिशील आलू उत्पादकों, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, आलू विक्रेता/निर्यातक तथा आलू आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाय।
- आलू विकास बोर्ड में क्रय–विक्रय की गतिविधियों की अहम भूमिका होगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के सहयोग एवं सहभागिता बनाने पर विचार किया जाय।
- आलू विकास बोर्ड के लिए सहभागी क्षेत्रों से आमंत्रित किये गये मौखिक एवं लिखित सुझावों को आलू विकास बोर्ड के कार्य–कलापों में सम्मिलित कर लिया जाय।
- जनपद आगरा के प्रगतिशील आलू कृषकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आलू बीजों की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में उसे आश्वस्त किया गया कि आलू बीजों का आबंटन जनपद की माँग एवं उपलब्धता के अनुसार कर दिया जाय।

अन्त में डॉ. आर.के. तोमर, उप निदेशक (आलू) द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

→

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र.

2, सप्रू मार्ग, लखनऊ

पत्रांक – आलू 539–57/आलू विकास बोर्ड/बैठक/दिनांक 12, जुलाई 2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र., शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उ.प्र. राज्य कृषि उत्पादन, मण्डी परिषद, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
3. उप निदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा।
4. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ।
5. श्री पुष्पेन्द्र जैन, प्रदेश महासचिव, आलू किसान विकास समिति (रजि.), आगरा।
6. श्री मनोहर सिंह चौहान, आलू उत्पादक कृषक एवं आलू ट्रेडर्स, आगरा।
7. श्री माधवेन्द्र, प्रगतिशील कृषक, हसनपुर, खन्दौली, आगरा।
8. श्री नेमीचन्द्र राजपूत, निर्यातक एवं महामंत्री, उ.प्र. पोटैटो फैसलीटेशन सोसायटी, मण्डी परिषद, उ.प्र.।
9. श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन।
10. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आलू उत्पादक, ग्राम दौलतपुर, सूरतगंज, बाराबंकी।
11. श्री सुरेन्द्र प्रकाश, प्रगतिशील, कृषक, बाराबंकी।
12. श्री बृज किशोर वर्मा, प्रगतिशील कृषक, बाराबंकी।
13. श्री विजय कान्त मिश्रा, आलू उत्पादक, ग्राम व पोस्ट : उधरनपुर, वि.ख. – शादाबाद जनपद हरदोई।
14. श्री लोकेन्द्र, एम.टी.आर.।
15. श्री विनय कुमार सिंह, सोनभद्र।
16. श्री गोविन्द स्वरूप धीरानी, महासचिव, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन।
17. श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रतिनिधि, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन।
18. श्री प्रकाश लोहिया, एम.डी., मैरीनो इण्डस्ट्रीज लि. हापुड़।
19. श्री सुनील कुमार, मै. ए.यू.ई.वी.एस.एस. लि. प्रतापपुर, मेरठ।

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित